त्रिपुरा के नतीजों ने साबित किया क्षेत्रीयता पर चढ़ता राष्ट्रीयता का रंग

त्रिपुरा के नतीजे अभूतपूर्व हैं। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां शून्य से अपनी शुरुआत की थी और पांच साल बाद लगभग 50 फीसद वोट पाकर सत्ता के शिखर तक पहुंच गई है। इसे चुनावी लोकतंत्र में चमत्कार ही कहा जाना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा ने यहां वाममोर्चे को जबर्दस्त पटखनी दी है, उससे दिल्ली की टीवी डिबेटों में बैठने वाले राजनीतिक पंडित व विश्लेषक भी भौंचक हैं। इस जीत के पीछे मोदी का नेतृत्व और अमित शाह की सटीक व्यूह रचना को तो श्रेय जाता ही है, लेकिन सही मायनों में त्रिपुरा की जीत का बड़ा श्रेय वहां दो साल से डेरा जमाए बैठे संघ के सुनील देवधर, विप्लव देव और कांग्रेस ने जिसे थाली में परोसकर दिया था, उस हेमंत बिस्वसर्मा को जाता है।

भारतीय जनता पार्टी जिस मंथर लेकिन जड़ें जमाती हुई गति से चल रही है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व के लिए अभी पार पाना बहुत आसान नहीं होगा। त्रिपुरा के नतीजे कर्नाटक में भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेंगे। भाजपा कर्नाटक में इसे भी प्रचारित करेगी कि कांग्रेस की शीर्ष नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पास भी इतने राज्य नहीं रहे और यदि 18 राज्य मान भी लें तो वह भी साम, दाम, दंड व भेद से हथियाए हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की झोली में अपने दम पर 20 राज्य डाल दिए हैं। जो भी हो, यह साबित हो गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत से शुरू हुआ भाजपा का अभियान अब वाम मुक्ति की ओर बढ़ने लगा है। त्रिपुरा हारने के बाद वाम केवल केरल में बचेगी जहां हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है। पश्चिम बंगाल हारने के बाद से अंदरूनी लड़ाई में बिखर रहे वाम के लिए अब अस्तित्व का संकट है। उनके लिए यह सोचने का वक्त है कि उनकी रीति नीति समाज से जुड़ी भी है या नहीं। जबकि पड़ोस के पश्चिम बंगाल में काबिज तृणमूल कांग्रेस को यह संकेत डरा सकता है।

पूर्वोत्तर में जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उसका सूत्रपात 2014 में ही हो चुका था। तकरीबन तीन साल पहले मोदी व शाह ने मिलकर उत्तर पूर्व को चलो पलटाई का जो नारा दिया था, वह साकार हो गया है। इस जीत का असली श्रेय संघ, भाजपा और वहां के प्रभारियों को जाता है। 2014 में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पश्चिमी राज्यों में विकास तो गति पकड़ चुका है, लेकिन पूर्वी राज्य इस विकास की गति से अछूते रह गये हैं और कांग्रेस और वामपंथी सदैव इससे मुंह मोड़ते रहे हैं। हमारा काम होगा कि इन पूर्वी राज्यों को भी देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़े। दरअसल, ईमानदारी का मुखौटा ओढ़कर राजनीति करने वाले वामदलों का बचा खुचा मुलम्मा भी त्रिपुरा की लैंड स्लाइड विक्ट्री के बाद उतर चुका है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में दशकों से काबिज वामदल नेतृत्व तो ईमानदार चेहरा रखते थे, लेकिन उस ईमानदारी की आड़ में भ्रष्टाचार और लूट की हदें पार करते थे। इसीलिए लगभग तीन दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में काबिज वाम मोर्चे को ममता बनर्जी की अनगढ़ पार्टी ने जोरदार पटखनी दे दी। यहां यह भी याद रखना चाहिए, कि ज्योति दा और बुद्धदेव भट्टाचार्य भी ईमानदारी के पुतला ही थे। उसी कड़ी में त्रिपुरा के माणिक सरकार भी आते हैं। इसीलिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्वोत्तर में मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद कहा है कि भारत देश की राजनीति के लिए लेफ्ट अब कहीं से भी राइट नहीं बचा है। महान वामपंथी विचारक और सोवियत नेता ट्राटस्की ने कहा था, कि वह समय दूर नहीं, जब वामपंथी विचारधारा न्यूजपेपर की हेडलाइनों से निकलकर केवल पाठ्यपुस्तकों तक सिमट जाएगी।

अराकू घाटी में विकसित कॉफी के लिए प्रीमियम टैग

कॉफी बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित अराकू घाटी के जनजातीय समुदायों द्वारा विकसित की जाने वाली कॉफी की विशिष्ट पहचान के संरक्षण के लिए भौगोलिक संकेतों के तहत अराकू कॉफी के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

इस आशय की जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सी.आर. चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

केन्द्र सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए 'एकीकृत कॉफी विकास परियोजना' क्रियान्वित कर अराकू घाटी में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इस योजना में पुनर्रोपण एवं विस्तार, जल संचयन एवं सिंचाई बुनियादी ढांचे का निर्माण और कॉफी एस्टेट के परिचालन के मशीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन और संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए तकनीकी सहायता भी दी जाती है। एसएचजी और उत्पादक समूहों के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये का प्रोत्साहन देकर कॉफी बोर्ड अराकू कॉफी के सामूहिक विपणन को सुविधाजनक बना रहा है।

अराकू घाटी क्षेत्र में उत्पादित होने वाली अराबिका कॉफी एक उत्तम गुणवत्ता वाली विशेष कॉफी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गई है। कॉफी बोर्ड ने देश में उत्पादित होने वाली विभिन्न कॉफी किस्मों के लिए उनकी भौगेलिक विशिष्टता के आधार पर विशेष लोगो विकसित किए हैं।

कॉफी बोर्ड हर साल आयोजित की जाने वाली 'फ्लेवर ऑफ इंडिया-द फाइन कप अवार्ड' प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कॉफी उत्पादकों को प्रोत्साहित करता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कॉफी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू चंडीगढ़ से प्रस्थान पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वी.पी. सिंह बदनोर, हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर उन्हें विदा करते हुए।

चुनौतियों के बीच एक बेहतर बजट

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का यह अंतिम बजट एक लोकलुभावन बजट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते कुछ महीनों में विभिन्न वर्गों को लुभाने के लिए जो प्रमुख घोषणाएं की हैं, उन्हें साधने के साथ-साथ हर वर्ग एवं क्षेत्र को लाभ देने के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। प्रदेश सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं हेतु सराहनीय बजट आवंटन किया गया है। निस्संदेह प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री जयंत मलैया कृषि व ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते नजर आए। केंद्र सरकार की तरह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य घोषित करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों व खेती के लिए बजट में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इस तरह प्रदेश सरकार ने बजट के माध्यम से किसानों को साधने की हरसंभव कोशिश की है। बजट में किसानों और कृषि के लिए 37,498 करोड़ रुपए का प्रावधान सराहनीय कहा जा सकता है। अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु डिफॉल्टर किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी अच्छा है। बजट में फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार कृषक समृद्धि योजना लागू करने जा रही है। नए बजट में करीब दो लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई नवीन माइक्रो सिंचाई सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। भावांतर भुगतान योजना के दायरे को भी बढ़ाया गया है। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपए और नई कृषक समृद्धि योजना के लिए 3650 करोड़ रखे गए हैं। कृषि प्रोत्साहन योजना के तहत गेहूं और धान पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बजट में प्रदेश की करीब 50 मंडियों को ई-सेवा से जोड़ने के प्रावधान किए गए हैं। फसल बीमा को कारगर बनाने, किसानों को बिजली, खाद व राहत वितरण के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि रखी गई है।

इस बजट में गरीबों के कल्याण पर भी जोर है। नए वित्त वर्ष में दीनदयाल रसोई योजना के तहत प्रारंभ में प्रदेश के चार बड़े शहरों के गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना को कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) कोष से संचालित किया जाएगा। बाद में योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की है, जो आज के समय के हिसाब से नाकाफी लगती है। समाज में विधवाओं की कमजोर स्थिति को देखते हुए शासन ने सेवारत और पेंशनभोगियों को छोड़कर सभी विधवाओं को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 1,501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में गरीबों एवं पिछड़े वर्ग की छोटी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए खासतौर पर नई योजनाओं को शामिल किया गया है। इन वर्गों के लिए स्वरोजगार की ऐसी नई योजनाएं बजट में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें सरकार थोड़ा पैसा देकर हितग्राही की आमदनी बढ़ा सके। स्वरोजगार के लिए बजट आवंटन दोगुना किया गया है। मुख्यमंत्री ऋणी सेवाधार योजना भी शुरू की गई है। यद्यपि प्रदेश के खजाने की खस्ता हालत है, फिर भी सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों को साधने के लिए खजाने का मुंह खोलने से पीछे नहीं हटी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुशियां देने के प्रावधान भी नए बजट में किए गए हैं। इस बजट में प्रदेश के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी गई है। स्मार्ट सिटी के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में भोपाल व इंदौर में मेट्रो ट्रेन, जबलपुर और ग्वालियर में नए बायपास के निर्माण की शुरुआत की बात कही गई है। सड़क निर्माण और पुल निर्माण के लिए बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए 855 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जीएसटी के बाद उद्योगों की मुश्किल कम करने के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

शिक्षित-अशिक्षित व अल्पशिक्षित युवाओं की रोजगार जरूरतों के लिए कौशल-प्रशिक्षण के प्रयासों को अमलीजामा पहनाने के लिए विशेष बजट आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आगामी वित्त वर्ष से शुरू की जाएगी व इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि का पृथक कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। इस योजना के तहत 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे।

यद्यपि यह बजट हमारे प्रदेश के गांव, किसान, गरीब समेत विभिन्न् वर्गों को राहत पहुंचाता लगता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी दिखाई दे रही हैं। इस बजट में उद्योग-कारोबार और निर्यात वृद्धि के लिए पर्याप्त आवंटन और योजनाएं नहीं हैं, जो कि अखरने वाली बात है। रोजगार और स्वरोजगार के मद्देनजर भी वित्त मंत्री से और अधिक कदमों की उम्मीद की जा रही थी। प्रदेश सरकार के कई स्वप्निल लक्ष्यों के लिए इस बजट में आवंटन बहुत छोटी-छोटी राशियां लिए हुए हैं।

निश्चित रूप से प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया के समक्ष जहां एक ओर इस बजट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समय-समय पर की गई विभिन्न् घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने व विभिन्न् वर्गों की कई अपेक्षाओं को पूरा करने की बड़ी चुनौती थी, वहीं उन्हें राजकोषीय संतुलन भी साधना था। प्रदेश सरकार पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में कहना होगा कि वित्त मंत्री ने सीमित वित्तीय संसाधनों का चतुराईपूर्वक संतुलित उपयोग करते हुए किसान, गरीब कल्याण और बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता देने वाला बेहतर बजट प्रस्तुत किया है।

वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश करते हुए राजकोषीय बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्देशों का भी ध्यान रखा है। राजकोषीय घाटा प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 फीसदी की सीमा के अंदर ही रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार के इस बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार बजट योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह करेगी और अतिरिक्त संसाधन किस तरह जुटाएगी।

प्रधानमंत्री आज केन्द्रीय सूचना आयोग के नए भवन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिल्ली के मुनिरका में केन्द्रीय सूचना आयोग-सीआईसी के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस नए भवन से आयोग अपना कामकाज एक स्थान से संचालित कर सकेगा। इससे पहले आयोग का कामकाज किराए के दो भवनो से संचालित होता रहा है। सीआईसी का नया भवन हरित प्रौद्योगिकी से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा बनाया गया है। पांच मंजिला इस भवन में केन्द्रीय सूचना आयोग के सभी सुनवाई कक्ष अत्याधुनिक आईटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली से लैस हैं। सीआईसी सूचना अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित शीर्ष अपीलीय निकाय है।

राष्ट्रपति ने वियतनाम के राष्ट्रपति की मेजबानी की ; कहा, भारत और वियतनाम की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज (3 मार्च, 2018) राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति महामहिम ट्रान डई कुआंग की की मेजबानी की। उन्होंने उनके सम्मान में एक प्रीतिभोज का भी आयोजन किया।

वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने वियतनाम को जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में ठोस परिणाम सुनिश्चित करने में एक समन्वयक देश की भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच 2000 सालों से पुराना सभ्यातागत संबंध हैं। बौद्ध धर्म, हिन्दू चम्पा सभयता और हमारे साझा दर्शन ने हमारे समान रिश्तों को सुदृढ़ बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे नेताओं ने 2020 तक 15 बिलियन डॉलर का व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों में दोगुनी तेजी लानी होगी।

महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा पर समान दृष्टिकोण हैं। बाद में, अपने प्रीतिभोज भाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के नेता महात्मा गांधी और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह आधुनिक युग में हमारे संबंधों में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं।

महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और वियतनाम के बीच एक मजबूत साझीदारी हमारे लोगों के लिए तथा व्यापक क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना और एनएफआरए के लिए अध्यक्ष के एक पद, पूर्णकालिक सदस्यों के तीन पदों व एनएफआरए के लिए सचिव का एक पद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस निर्णय का उद्देश्य लेखापरीक्षा के कार्य, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए परिवर्तनों में से एक है, इसके लिए एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में एनएफआरए की स्थापना करना है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की विशिष्ट सिफारिशों (उसकी 21वीं रिपोर्ट) में यह प्रावधान करना शामिल था।

इस निर्णय से विदेशी/देश में निवेश में सुधार, आर्थिक विकास में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप कारोबार के वैश्वीकरण को अनुसमर्थन तथा लेखापरीक्षा व्यवसाय के सतत विकास में सहायता मिलेगी।

अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत सनदी लेखाकारों और उनकी फर्मों की जांच करने के लिए एनएफआरए का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों तथा वृहद गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को कार्य क्षेत्र में लाना है, जोकि नियमों में निर्धारित अपेक्षा के अयोग्य है। केन्द्र सरकार ऐसे अन्य निकायों की जांच के लिए भी कह सकती है, जहां सार्वजनिक हित अंतर्विष्ट हो।

चाटर्ड अकांटेंट अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार आईसीएआई की व्याप्त विनियामक भूमिका सामान्य रूप से उनके सदस्यों तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा के संबंध में विशेष रूप से जारी रहेंगी और थ्रेशहोल्ड सीमा से नीचे सार्वजनिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को नियमों में अधिसूचित किया जाएगा।

गुणवत्ता पुनरीक्षा मंडल (क्यूआरबी) की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, निर्धारित थ्रेडहोल्ड से कम सार्वजिनक गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में गुणवत्ता लेखापरीक्षा भी जारी रहने के साथ-साथ उन कंपनियों की लेखापरीक्षा के संबंध में भी एनएफआरए द्वारा क्यूआरबी को यह कार्य सौंपा जा सकता है।

लेखापरीक्षा घोटालों के दृष्टिगत विश्व में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महसूस की गई जरूरत के मद्देनजर एनएफआरए की स्थापना की जरूरत नहीं है, जिसका उद्देश्य इसका विनियमन कर रहे तंत्र से इतर स्वतंत्र विनियामकों को स्थापित करना और लेखापरीक्षा मानकों को लागू करना, लेखापरीक्षा की गुणवत्ता व लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना है। अतएव, कंपनियों की वित्तीय स्थिति के प्रकटीकरण में निवेशक व सार्वजनिक तंत्र का विश्वास बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कर्नाटक के तुमकुरु में युवा सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने - युवा शक्ति- नव भारत के लिए एक विजन- थीम पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज कर्नाटक के तुमकुरु में युवा सम्मेलन को संबोधित किया।

तुमकुरु में युवा सम्मेलन का आयोजन शिकागो में स्वामी विवेकानंद के संबोधन की 125वीं जयंती के साथ साथ सिस्टर निवेदिता की 150ीं जयंती का समारोह मनाने के लिए तुमकुरु में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की रजत जयंती समारोहों के अवसर पर किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक संभव है, वह युवाओं से अधिकतम मिलने का प्रयास करते हैं जिससे कि वे उनकी आकांक्षाओं एवं उम्मीदों को समझ सकें एवं उसके अनुरूप कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि आज के स्मरणोत्सव का फोकस स्वामी विवेकानंद हैं।

उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर एक संयुक्त संकल्प था। इसमें सामाजिक सुधारों पर प्रयास शामिल था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के भावनात्मक एकीकरण के लिए संकल्प किया है और इसे सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल एकीकरण ही उग्रवाद का मुकाबला कर सकता है।

उन्होंने युवाओं से एक संकल्प करने और इसे अर्जित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने को कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित कर देनी चाहिए।

इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना, स्वरोजगार एवं कौशल विकास की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवा बेहतर वर्तमान और भविष्य के लिए अतीत से अनुभव ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं।

डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी -प्रदर्शित कर रही है 'भारत-एक उभरता रक्षा विनिर्माण हब'

डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी पहली बार विश्व के सामने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। यह प्रदर्शनी के टेग लाइन में परिलक्षित है जो 'भारत-एक उभरता रक्षा विनिर्माण हब' है। डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी भारत की सभी तीन सेनाओं -थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना की कई रक्षा प्रणालियों एवं कंपोनेंट के एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में ब्रांडिंग करेगी। यह प्रदर्शनी जहां भारत की उल्लेखनीय सार्वजनिक क्षेत्र की ताकतों को प्रदर्शित करेगी, वहीं यह भारत के बढ़ते निजी क्षेत्र उद्योग को भी सामने लाएगी तथा कंपोनेंट एवं सब-सिस्टम्स के लिए एमएसएमई आधार को विस्तारित करेगी।

डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को विभिन्न फ्लाइंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदर्शित करेगी। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त, यह प्रदर्शनी घरेलू निजी उद्योग एवं एयरो-कंपोनेंट उद्योग को भी बढ़ावा देगी।

डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी का आयोजन समुद्र के तट चेन्नई से महाबलीपुरम के रास्ते पूर्वी तट पर किया जा रहा है, यह भारतीय नौसेना को अपने घरेलू डिजाइन एवं विनिर्माण क्षमताओं को भी प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी। भारत गर्वपूर्वक जहाज निर्माण में अपनी नौसैनिक डिजाइनिंग क्षमताओं को प्रस्तुत करेगा।

ज्हां तक भूमि प्रणालियों का प्रश्न है तो भारत डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी में अपनी 155 एमएम एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन (एटीएजी) का अनावरण करेगा। यह पहली बार है कि भारत के पास अपनी खुद की एटीएजी है जिसकी डिजाइन एवं जिसका विकास कल्याणी ग्रुप, टाटा पावर एवं ओएफबी के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा किया गया है।

भारत अपनी मिसाइल एवं रॉकेट विनिर्माण क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेगा जिसमें सतह से वायु, वायु से वायु एवं समुद्र से वायु समेत सभी प्रकार के हमलों के लिए उपलब्ध ब्रह्मोस भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी का एक बड़ा आकर्षण आकाश मिसाइल सिस्टम भी होगा।

भारत को एक उभरते रक्षा उत्पादक हब के रूप में रेखांकित करने पर फोकस को देखते हुए डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी में कम से कम आधा स्थान घरेलू प्रदर्शकों के लिए निर्धारित किया गया है। यह डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने एवं रक्षा विनिर्माण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ समेकित हसेने का अब तक का सबसे बढ़ा अवसर उपलब्ध कराएगा।

महिला विकास की बातें हैं, बातों का क्या!

इस समय जब वसंत अलविदा ले रहा है और एक नया संवत्सर दहलीज पर खडा है, वाक्चीर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सरकार के सालाना आर्थिक सर्वेक्षण मसौदे को पहली बार एक गुलाबी जिल्द में प्रस्तुत किया। पर यह गौरतलब है कि उस मसौदे के अनुसार भारत की अपेक्षित कुल आबादी में से 6 करोड़ तीस लाख महिलाएं गायब हैं। इस गैरहाजिरी की जो मोटी वजह प्राप्त आंकड़ों से मिल रही है, वह यह कि महिला-बच्चियों के प्रति विषमता मिटाने में तमाम कानूनी सुधार और आकर्षक सरकारी स्कीमें व सबसिडियां भी भारतीय समाज के भीतर छुपी उस खामोश कायरता को मिटाने में विफल हैं, जो घर से बाजार तक पुरुष आधिपत्य की पक्षधर और गहरी पुत्रकामना से ग्रस्त है। पुरुष को हर सकारात्मक गुण का अंतिम प्रमाण और पुत्र को कुलदीपक मानने की मानसिकता की वजह से कन्याशिशु को संपन्नतम राज्यों में भी निरक्षर या साक्षर परिवार एक अनचाहा बोझ मानते हैं और अगर वह अभागी किसी तरह जनम गई, तो भी उसे वंचित-उपेक्षित जीव का दर्जा मिलता है जो भाई की तुलना में एक अनचाही संतति ही है। कोख में कन्या भ्रूण की अवैध हत्या और जन्म के बाद लगातार पोषाहार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गहरी उपेक्षा शहर, गांव हर कहीं हो रही है और लड़कियों की तादाद लगातार बेटों की तुलना में घट रही है। इससे देश की समग्र आबादी में पुरुषों और महिलाओं के बीच आबादी का संतुलन बुरी तरह गड़बड़ा गया है। कई राज्यों में बहुएं खोजे नहीं मिल रहीं और सामूहिक बलात्कार तथा लड़कियों को जबरन अगवा करने की घटनाएं हर राज्य में बढ़ रही हैं। आने वाले समय में देश को इस विसंगति की और भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज से कोई दो दशक पहले ही जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं की लगातार और चिंताजनक तौर से घटती आबादी के बारे में चेतावनी दे दी थी। पर मौजूदा सरकार ने उनसे विमर्श करने के बजाय महिलाओं के बारे में सकारात्मक चिंतन से जुड़े रहे इस ख्यातनाम बुद्धिजीवी को नालंदा विवि के शीर्ष मानद पद से भी चुपचाप हटा दिया। आज विश्व स्वास्थ्य और महिला विकास पर संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों द्वारा किए गए सर्वे में भारत के गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरीखे नवसमृद्ध या केरल और असम सरीखे प्राचीन मातृसत्ताक परंपरा वाले राज्यों के समाज में लड़कियों की तादाद में चिंताजनक गिरावट दर्ज हो रही है। और कई सामाजिक, शैक्षिक विकास की सीढ़ियों में भारत का नीचे सरकना हमारे राज-समाज की प्रतिगामी सोच व विकास की कथित प्राथमिकताओं के बाबत कई तीखे सवाल दुनिया में पैदा कर रहा है। हमारा अपना राज-समाज और महिला सशक्तीकरण का ब्लूप्रिंट बनाने वाली सरकारी संस्थाएं और संगठन खुद सरकार के ताजा सर्वेक्षण की स्थापना से क्या कोई सबक लेंगे, यह अभी देखा जाना है। किंतु सर्वेक्षण में संतति के जन्म के क्रम की पारिवारिक जांच से यह साफ जाहिर होता है कि आज हमारे देश में 25 साल से कम उम्र की कम से कम 2 करोड़ दस लाख युवतियां ऐसी हैं, जिनका जन्म परिवार में इस बार शायद बेटा हो, की कामना के तहत यानी माता-पिता के अनचाहे हुआ है। जन्मना उन पर अवांछित होने का धब्बा लगने से उनकी परवरिश भी मन मारकर ही की जाती है। इससे अधिकतर लड़कियां रक्ताल्पता और कमजोर हड्डियों के साथ जवान हो रही हैं। इसका प्रसूतिकालीन मातृमृत्यु से सीधा नाता है। जहां तक युवा पीढ़ी की सोच की बात है, वहां भी लड़कियों को लेकर अक्सर प्रतिगामी सोच नजर आती है, जबकि यह उम्र वीर बनकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़े होने की मानी जाती है। सभी राज्यों के युवा वर्ग में खूब सारा पैसा जल्द कमा लेने की अदूरदर्शी कामना तो बढ़ी पाई गई है, लेकिन बेटों में दहेज की हवस, खुद को परिवार का इंजन समझना और महिला पर हाथ उठाना अभी भी दर्ज हो रहा है। पोषाहार से शिक्षा और संपत्ति के बंटवारे से स्वास्थ्य तक हर कहीं बेटों को बेटियों पर तरजीह दी जा रही हो तो इस मानसिकता से चकित नहीं होना चाहिए।

सूचना

कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई-मेल पर ही भेंजे :

alpaviram@gmail.com